



अधिकतम : 23° C
न्यूनतम : 11° C

खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

हल्द्वानी, बुधवार 26 नवम्बर 2025 हल्द्वानी संस्करण: वर्ष 23 अंक 91 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

shahtimes2015@gmail.com

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 6 विक्रमी सम्वत् 2082

4 जमादियुल उखरा 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित



दुनिया के लिए मार्गदर्शक है भारत का संविधान: बिरला

पेज 2



टी-20 विश्वकप: 15 फरवरी को होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़त

खेल टाइम्स



यूपी विधानसभा चुनावों में ओवैसी का अखिलेश यादव से मुलाकात का वादा

सम्पादकीय



पाकिस्तान ने की आधी रात अफगानिस्तान में तीन एयरस्ट्राइक, 10 की मौत

पेज 12

संक्षिप्त समाचार

ज्वालामुखी विस्फोट के कारण प. एशिया की कई उड़ानें रद्द नई दिल्ली।

हेली गुब्बो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले राख के बादलों की वजह से भारत से पश्चिम एशियाई शहरों को जाने वाली कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। टाटा समूह की विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया ने मंगलवार को बताया कि उसने सोमवार और मंगलवार को अबतक कुल 13 उड़ानें रद्द की हैं। अकासा एयर ने भी बताया कि उसने सोमवार और मंगलवार को जेद्दा, कुवैत और अबु धाबी को जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने बताया कि सोमवार को सात उड़ानें रद्द की हैं। इनमें अमेरिका के नेवाक से दिल्ली, न्यूयॉर्क से दिल्ली, दुबई से हैदराबाद, कतर के दोहा से मुंबई, दुबई से चेन्नई, दम्पम से मुंबई और दोहा से दिल्ली को उड़ानें शामिल हैं। एयरलाइंस ने मंगलवार को चेन्नई-मुंबई, हैदराबाद-दिल्ली, मुंबई-हैदराबाद, हैदराबाद-मुंबई, मुंबई-कोलकाता और कोलकाता-मुंबई उड़ानें रद्द की हैं। एयरलाइंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वह जो विमान ज्वालामुखी से निकले राख के बादलों वाले इलाकों से होकर गुजर रहे हैं उनका जांच की जा रही है। उसने बताया कि प्रभावित यात्रियों को ग्राउंड टीम हरसंभव सहायता मुहैया कराई जा रही है।

ज्वालामुखी विस्फोट के कारण फिलहाल चिंता की बात नहीं नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह इथोपिया में हेली गुब्बो ज्वालामुखी के फटने के बाद स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और फिलहाल उड़ानों को लेकर चिंता की बात नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि ज्वालामुखी से निकले राख के बादल पूर्व दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसे में एटीसी, मौसम विभाग, विमान सेवा कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय विमानन एजेंसियों के साथ वह भी निर्बाध समन्वय सुनिश्चित कर रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने पायलटों के लिए जरूरी नोटिस जारी किया है।

राजस्थान-मप्र के 16 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे नई दिल्ली।

देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और सर्द हवाओं से मैदानी राज्यों में हिटुरन बढ़ने लगी है। राजस्थान में सोमवार को कोटा, उदयपुर समेत कई जिलों में दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहा। फतेहपुर में सबसे कम, 5.8 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश में भी सर्द हवाओं ने हिटुरन बढ़ा दी है। नागौर, राजगढ़, नरसिंहपुर और रीवा में सोमवार को तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रहा। भोपाल सहित कई जिलों में लगातार तीसरे दिन बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने राज्य में अगले चार दिन तक शीतलहर से राहत की संभावना जताई है। इधर, बिहार में सर्दी के साथ घने कोहर का असर बढ़ गया है। बीते दिन, पटना, खगड़िया, गोपालगंज, सारण, बेगूसराय समेत 10 शहरों में सुबह-सुबह घना कोहरा देखने को मिला।

हिरासत में हिंसा और मौत सिस्टम पर धब्बा: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत की सख्त टिप्पणी: देश नहीं करेगा बर्दाश्त

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में हिंसा और मौत हमारी व्यवस्था पर एक 'बड़ा दाग' है और देश अब इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा।

सुप्रीम कोर्ट एक मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है, जो देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी के ठीक से न चलने से जुड़ा है। अदालत ने इस दौरान राजस्थान में आठ महीनों में 11

हिरासत में मौतों पर गहरी चिंता जताई। दो जजों की बेंच न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने मामले में कहा कि देश अब ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा।

यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौत नहीं हो सकती। वहीं सॉलिसिट जनरल गुप्ता मेहता ने कहा कि हिरासत में मौत को कोई भी व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन कोर्ट इस बात से नाराज हुआ कि केंद्र सरकार ने अब तक अपनी अनुपालन

रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। अदालत ने इस पर तीखा सवाल किया और पूछा कि केंद्र सरकार इस

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में आठ महीनों में 11 हिरासत में मौतों पर गहरी चिंता जताई

अदालत को हल्के में क्यों ले रही है? इसके बाद केंद्र ने तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा देने का वादा किया।

आर्मी अफसर की बर्खास्तगी सही, अपील खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आर्मी के एक पूर्व ईसाई अफसर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। अफसर पर आरोप था कि उसने अपने तैनाती स्थल पर रेजिमेंट की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से इन्कार किया था। इसके बाद आर्मी ने उसे बर्खास्त कर दिया। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने अफसर को आर्मी के लिए मिस फिट माना और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह

कहा- आप सेना के लायक नहीं, धार्मिक आदेश न मानने पर सेना से निकाले गए थे

आचरण गंभीर अनुशासनहीनता है और सेना जैसी संस्था में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह मामला 2017 का है। अफसर सैम्युअल कमलेशन 3तक कैवेलरी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बने। उनकी यूनिट में मंदिर और गुरुद्वारा था, जहां हर हफ्ते धार्मिक परेड होती थी। वे अपने सैनिकों के साथ वहां तक जाते थे, लेकिन मंदिर के सबसे अंदर वाले हिस्से में पूजा, हवन या आरती के दौरान जाने से मना करते थे। उनका कहना था कि उनकी ईसाई मान्यता इसकी अनुमति नहीं देती और उनसे किसी देवी-देवता की पूजा करवाना गलत है।

अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण की प्रक्रिया हुई पूरी

सदियों के घाव अब भर रहे हैं: मोदी

अयोध्या, वार्ता

राम मंदिर में ध्वजारोहण की प्रक्रिया पूरी हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपार जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा बहुत पुराना सपना अब पूरा हुआ। सदियों पुराने घाव थे अब वह धीरे-धीरे भरने शुरू हुए। पीएम ने कहा कि हम ऐसा समाज बनाएँ, जहाँ कोई गरीब न हो। कोई पीड़ित न हो। यह ध्वज युगों-युगों तक श्री राम के आदेशों और प्रेरणाओं को मानव मात्र तक पहुँचाएँ।

उन्होंने हर दानवीर, श्रमवीर, कारीगर, योजनाकार, वास्तुकार का अभिनंदन किया। यही वह नगरी है, जहाँ से श्रीराम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। विकसित भारत बनाने के लिए समाज की सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। यहाँ सप्त मंदिर बने हैं। यहाँ निषाद राज का मंदिर बना है, जो साधन नहीं साध्य और उसकी भावनाओं को पूजती है। यहाँ जटायु जी और गिलहरी की भी मूर्ति है, जो बड़े संकल्प की सिद्धि के लिए हर छोटे से छोटे प्रयास को दिखाती है। पीएम मोदी के बटन दबाते ही झंडा धीरे-धीरे ऊपर चढ़ता हुआ मंदिर के शीर्ष पर विराजमान हो गया। जैसे-जैसे झंडा ऊपर चढ़ता गया पीएम मोदी टकटकी लगाए उसे देखते रहे। पीएम मोदी इन पलों में भावुक नजर आए। ध्वजारोहण के समय सामने की कतार में साधु-संत बैठे हुए थे। वह भी भावुकता में अपने आँसू पोछते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में देश-दुनिया के करोड़

कहा- हमारा बहुत पुराना सपना अब पूरा हुआ, हम ऐसा समाज बनाएं, जहाँ कोई गरीब न हो



आठ हजार लोग आमंत्रित किए गए थे। निर्धारित शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्मध्वज फहराया। जैसे ही कंसरिया ध्वज पवन के संग लहराया, पूरा परिसर 'जय श्री राम' के उद्घोष से गुंज उठा। क्षण भर में वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया और श्रद्धालुओं की भावनाएं उमंग में बदल गईं। धर्मध्वज फहराने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच व्यापक पूजन-अर्चन सम्पन्न हुआ। यज्ञकुंडों से उठती आहुतियाँ की सुगंध और नगाड़ों की गूँज ने समारोह को भव्यता प्रदान की। पीएम ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र को सनातन परंपरा की अखंडता,

बटन दबते ही मंदिर के शीर्ष पर फहराया ध्वज, मोदी हुए भावुक, आँसू पोछते दिखे साधु-संत

ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज

आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष-बिंदु की साक्षी बन रही है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर ध्वजारोहण उत्सव का यह क्षण अद्वितीय और अलौकिक है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वज नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये ध्वज संघर्ष से सुजन की गाथा है, सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है, संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणीति है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था, आज वह फहरा रहा है। इस भगवा ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कांतिविक्रम वृक्ष है। यह वृक्ष रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। यह वह वृक्ष है जिसके लिए कहा जाता है, कि वृक्ष सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर, फल भी दूसरों के लिए देते हैं। जाते जितनी कठिनाईयाँ हों, सूर्य भगवान उस संकल्प का प्रतीक है। इसमें सिर्फ एक ही पहिना है। जैसे सपना उन लोगों ने देखा था, बिल्कुल वैसा ही या यूँ कहें कि उससे भी भव्य मंदिर बन गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन में एक नई उर्जा दिखाई दी।

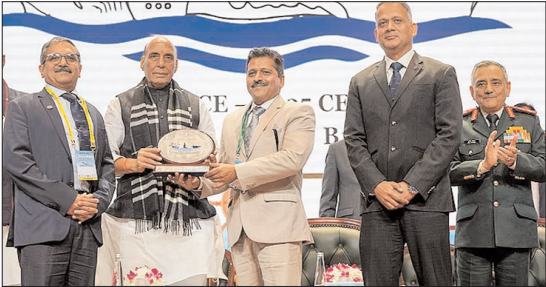
अब भारत खरीदार नहीं, तकनीक का निर्माता: रक्षा मंत्री

राजनाथ बोले: देश में स्वदेशीकरण आंदोलन चल रहा है, भारत की समुद्री शक्ति में हुई बढत

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में आयोजित भारतीय नौसेना के सेमिनार 'स्वावलंबन 2025' में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता और बदलते रक्षा ढांचे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि तकनीक बनाने, विकसित करने और निर्यात करने वाली ताकत बन रहा है। उनके मुताबिक देश में चल रहा स्वदेशीकरण आंदोलन सिर्फ नीतियों का परिणाम नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, इन्वेंटर्स, स्टार्टअप्स और युवाओं की कड़ी मेहनत का प्रमाण है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आयातक नहीं, बल्कि निर्माता और अनुयायी बनते हुए दुनिया को नई दिशा दिखा रहा है। उन्होंने बताया कि इन्वेंशन और प्रोटोटाइप से यह साबित कर दिया है कि भारत अब तकनीक का उपभोक्ता नहीं,



बल्कि निर्यातक बनने की राह पर मजबूती से आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन वास्तविक स्वावलंबन की ओर बढ़ते राष्ट्रीय संकल्प का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को विदेशी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता कम करनी होगी। उन्होंने बताया कि किसी भी बड़े उपकरण को विदेश से

खरीदना सिर्फ तत्काल लागत का मामला नहीं होता, बल्कि उसके रखरखाव, मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दीर्घकालिक लागत भी देश को झेलनी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने मजबूत और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत पर जोर दिया। उनके अनुसार भारत की सुरक्षा प्रणाली तभी मजबूत होगी, जब

भारत रक्षा क्षेत्र में आयातक नहीं, बल्कि निर्माता और अनुयायी बनते हुए दुनिया को नई दिशा दिखा सके

उसका तकनीकी ढांचा पूरी तरह भारत में विकसित और संचालित हो। स्वावलंबन 2025 में बोलते हुए सिंह ने कहा कि भारत आज समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसमें नौसेना के साथ देश के इन्वेंटर्स का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में बहु-उपयोगी तकनीक का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और भारत के युवा इन्वेंटर्स इसी दिशा में नई ऊँचाइयों को छू रहे हैं। सिंह ने कहा कि वह जब भी इन युवा शोषकताओं और स्टार्टअप्स से मिलते हैं, तो उनके अंतर समस्याओं को हल करने का आत्मविश्वास दिखाई देता है, जो उभरते भारत की पहचान है।

चुनाव आयोग अब बीजेपी

आयोग बन गया: ममता बनर्जी



कहा: यह निष्पक्ष संस्था नहीं, 10 टीएमसी सांसद 28 नवम्बर को इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे

सांसदों के नाम भेजे हैं। ममता ने पूछा- अगर एसआईआर का मकसद अवैध बांग्लादेशियों को हटाना है, तो बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? क्या बीजेपी यह स्वीकार कर रही है कि उसका 'डबल इंजन'

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई टली

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित मामले की सुनवाई को शुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्य सरकार ने आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा से जुड़े मुद्दों पर राज्य चुनाव आयोग के साथ परामर्श जारी रखने का हवाला देते हुए समय मांगा था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ को आयोग ने बताया कि 242 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव के लिए दो दिसम्बर की तारीख पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है।

विधानसभा में सीएम

सरमा बोले- सिंगर जुबीन का मर्डर हुआ

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि सिंगर जुबीन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी। सरमा ने कहा कि यह गैर इरादतन हत्या या आपराधिक साजिश नहीं, बल्कि साफ-साफ मर्डर था। सीएम ने दावा किया कि एक आरोपी ने सिंगर की जान ली। वहीं अन्य लोगों ने हत्या में उसकी मदद की।

असम विधानसभा में विपक्षी पार्टियां जुबीन की मौत पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लेकर आई थीं। जिस पर सीएम सरमा ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन जवाब दिया। सीएम ने बताया कि एसआईटी इवेंट के तहत इस मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया है, 252 गवाहों से पूछताछ की है और 29 सामान जब्त किए हैं। सीएम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 4 से 5 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जुबीन के निजी सुरक्षा अधिकारियों- नंदेश्वर बोरा और प्रवीण बेश्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जब पुलिस को उनके खातों से 1.1 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े वित्तीय लेनदेन का पता चला। गिरफ्तार किए गए सभी सात लोग अभी न्यायिक हिरासत में हैं।



मौत हादसा नहीं, एक आरोपी ने जान ली
बाकियों ने मदद की, अब तक सात गिरफ्तार

हुए थे। जुबीन की मौत मामले में पुलिस ने एनआईएफ इवेंट के आयोजक श्यामकान्त महंत, जुबीन के चचेरे भाई और पुलिस अधिकारी संदीप गर्ग, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके बेंड के दो मेंबर- शोखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा महंत को गिरफ्तार किया है। जुबीन के निजी सुरक्षा अधिकारियों- नंदेश्वर बोरा और प्रवीण बेश्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जब पुलिस को उनके खातों से 1.1 करोड़ रुपये से अधिक के बड़े वित्तीय लेनदेन का पता चला। गिरफ्तार किए गए सभी सात लोग अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

CMYK

बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बन्द



शाह टाइम्स संवाददाता

चमोली विधिव प्रसिद्ध चारधाम में शामिल बदरीनाथ धाम के कपाट मंगलवार को शीतकाल के बंद कर दिए। कपाट दोपहर 2:56 बजे विधि-विधान से बंद किए गए। करीब 5 हजार श्रद्धालु कपाट बंद करवा रहे थे। यहाँ, इस मौके पर बदरीनाथ के दरबार को फूलों से सजाया गया।

जिससे धाम को छूट देखते ही बन रही थी। श्रद्धालुओं को उपस्थिति में रातों रातों नवंबर में परंपरागत रीति रिवाज से कपाट बंद किए गए। मौके पर बदरीनाथ धाम को 12 फीटल गेट के फूलों से सजाया गया था, जबकि, सेना के सैनिक भी धाम और भगवान बदरीनाथ के दरबारों से सजाया गया।

धाम गुंज उठाएरपरा के अनुसार, उद्भव और कुबेर को प्रतिमाओं को गर्भगृह से बाहर लाया गया, जबकि, देवी लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान किया गया। भगवान बदरीनाथ को माया महिला मंगल दल की ओर से तैयार पुतल कनवल ओढ़ाया गया। शीतकालीन प्रवास स्थल की ओर खना हो गई है। इस बार करीब 16 लाख 60 हजार श्रद्धालु भगवानपुर क्षेत्र में शराव मिल स्थानों पर किए जाने, इकबाल, पुर झरबड़ा क्षेत्र में सिंघाई नहर

सीएम ने सुनी किसानों की समस्याएं लॉन में बैठकर लिया गन्ने का स्वाद

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को हरिद्वार जलपट्ट में आए गन्ना किसानों ने मुलाक़ात की। किसानों ने पराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य घोषित करने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर किसानों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गन्ना भी दिया, मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ ही भुप के बीच लॉन में ही बैठकर ही गन्ना का स्वाद लिया, साथ ही किसानों की मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया।

विधायक आदेश चौहान और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरनाथ के नेतृत्व में मिले गन्ना किसानों ने रायडी बग बागवाली पुल तक टयूबवे का निर्माण, इकबालपुर झरबड़ा भगवानपुर क्षेत्र में शराव मिल स्थानों पर किए जाने, इकबाल, पुर झरबड़ा क्षेत्र में सिंघाई नहर



सीएम धामी से मिला हरिद्वार के गन्ना किसानों का प्रतिनिधिमंडल

निर्माण और डोरबाला मिल पर किसानों का बकाया भुगतान करने

की मांग उठाई। किसानों ने पराई सत्र 2025-26 के लिए राय गन्ना परामर्शित मूल्य घोषित करने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने लॉन में बैठकर ही किसानों की मांगों को सुने हुए, गन्ना सुलभ सहित अन्य सभी मांगों पर सकारात्मक निर्णय

का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ जमीन पर बैठकर गन्ना का स्वाद भी लिया। इस मौके पर विधायक प्रदीप बजा, जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी के साथ ही पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी शामिल हुए।

शीतकालीन यात्रा से सालभर रोजगार के अवसर सृजित होंगे: महाराज

प्रमुख संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। उत्तराखण्ड के पर्यटन, धर्मस्थ, संस्कृति, पंचायतीराज, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण निर्माण एवं जलसंधि मंत्री शशीश महाराज ने बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ शीतकालीन चारधाम यात्रा के निर्विघ्न रूप से संपन्न होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी चारधाम यात्रा पर रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचेंगे। उन्होंने यात्रा व्यवस्था में सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, तीर्थ-पुरोहितों, होटल व्यवसायियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और यात्रियों को रातों रात पहुंचने वाले ट्रांसपोर्टों सहित यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का आधार व्यवस्था किया है। महाराज ने कहा कि है कि इस बार यात्रा में भी दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 51 लाख तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अब सरकार की पूर्ण ध्यान शीतकालीन यात्रा और उसकी व्यवस्थाओं पर है। अब चारधामों की पूजा अर्चना

शीतकालीन प्रवास स्थलों पर होगी जहां पर श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में पूजा पाठ कर दर्शन का साथ उठा सकते हैं। महाराज ने कहा कि उत्तराखण्ड की शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए 6 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा से देश विदेश के श्रद्धालुओं आने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर 2025 से शीतकालीन चारधाम यात्रा का श्री गंगोत्री हो चुका है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राय गन्ना के पूर्व में ही सभी वैधानिक पुरी कर रही है। महाराज ने कहा कि भगवान का दिव्य हमारे लिए दो शुरुआत अवसर का साक्षी बनने का अवसर है। एक ओर चारधाम यात्रा का संपन्न होना और दूसरी ओर अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर के विश्व पर भगवा खूब प्रसन्नता का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक है।

ग्रीन बिल्डिंग का कार्य अगले 6 माह में पूर्ण किया जाए: सीएस

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्वान को अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की उच्च स्तरीय संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया।

मुख्य सचिव ने ग्रीन बिल्डिंग निर्माण में जो रही रही पर गहरी राय रखी बताई। उन्होंने कहा कि ग्रीन बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी का पूर्णतया प्रोजेक्ट है। मुख्य सचिव ने 6 माह में पूरा करवा जहाँ शुरुआत में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रही जा रही 30 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का कार्य परिवहन निगम द्वारा किया जाए। उन्होंने वीएएमडी (एलडी स्क्रीन) एवं वायरलेस सेंसर को नगर



गया। उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में प्रत्येक कार्य को टारगेटसहित निर्धारित कर लगातार मॉनिटरिंग की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रही जा रही 30 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का कार्य परिवहन निगम द्वारा किया जाए। उन्होंने वीएएमडी (एलडी स्क्रीन) एवं वायरलेस सेंसर को नगर

3 शिफ्ट में कराया जाए कार्य, जिलाधिकारी देहरादून को लगातार मॉनिटरिंग के लिए निर्देश

निगम को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंट कमांड कंट्रोल सेंटर को आईटीडीए के अंतर्गत ही संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव निवेश कुमार झा, आरुच गढ़वाल विनय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून से सीईओ स्मार्ट सिटी सविन बंसल, अपर सचिव डॉ. इकबाल अहमद, एमडी परिवहन निगम जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यूकेडी नेता व पूर्व मंत्री दिवाकर भट्ट नहीं रहे

देहरादून। फील्ड मशीन के नाम से

विख्यात उत्तराखण्ड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता और उत्तराखण्ड के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे दिवाकर भट्ट का निधन हो गया। लंबी विपरीत के बावजूद उन्होंने हॉस्पिटल में अपने आध्यात्मिक राय 4.30 बजे आंखें संसल ले ले निधन हो चुका है। यह देहरादून के इंदिरा अस्पताल में भर्ती थे, 26 नवंबर को हरिद्वार के खड्डखड़ी रमेशान घाट पर उनका आंखें संसल कर दिया।

दिवाकर भट्ट उत्तराखण्ड क्रांति दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो राय आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में शामिल रहे। उन्हें अक्सर फील्ड मशीन के नाम से जाना जाता था, उनका जन्म साल 1946 में हुआ था, वे बुवाबाबा से ही उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन से सक्रिय थे। साल 1980-90 के दशक में राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरा बने। उन्होंने पर्यटन क्षेत्रों की



लम्बे समय से चल रहे थे बीमार, अपने आवास पर ली अन्तिम सांस, आज हरिद्वार में होगा अन्तिम संस्कार

उपेक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यक विभाजन बने। साल 2007-2012 के दौरान भगवा गन्वली की। साल 2002 में दिवाकर भट्ट यूकेडी के टिकट से देवगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, मगर हार गए, इसके बाद 2007 में यूकेडी से ही विधानसभा चुनाव

मुख्यमंत्री ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर जताया दुःख

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने

बरीष्ठ राय आंदोलनकारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने देवदार से अयोध्या को श्री चर्या में स्थान देने तथा शोक संतप्त परिवार को यह आशीर्वाद दूख सहने के लिए प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संतप्तों के हाथ दिवाकर भट्ट के निधन का समाचार पढ़ते दुःख है, राज्य निर्माण आंदोलन से लेकर जन सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव अविस्मरणीय रहेंगे।

मगर साल 2022 में बापय यूकेडी में लौटे आए। साल 2012 व 2017 में चुनाव लड़े, मगर हार का सामना करना पड़ा। वहीं, साल 2022 का चुनाव उन्होंने यूकेडी की तरफ से लड़ा, लेकिन हार गए। कैबिनेट मंत्री महाराज ने फील्ड मशीन के निधन पर शोक जताया देहरादून प्रेस के कैबिनेट मंत्री सहायका महाराज ने उत्तराखण्ड क्रांति दल को

राज्य निर्माण और विकास में योगदान के लिए दिवाकर भट्ट हमेशा याद किए जाएंगे: भट्ट

देहरादून। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यभा सोसाइटी महेंद्र भट्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री, यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष एवं बरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट के निधन पर दुःख व्यक्त किया है। अपने शोक संदेश में उन्होंने भट्ट के राज्य निर्माण आंदोलन एवं उसके विकास में दिए योगदान को अभूतपूर्व बताया। वहीं उनके निधन को राज्य के राजनैतिक, सामाजिक, जगत में बहुत बड़ी क्षति बताया। उन्होंने भट्ट को दृढ़ इच्छा शक्ति, खदरन, स्थानीय मुद्दों पर गंभीर एवं सविधानशील व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बताया।

कहा, उनके नेतृत्व में हुए श्रीवर्ष टांगू आंदोलन, राज्य निर्माण संघर्ष में मौल का पथर साहित्य हुआ था। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख मनवीर सिंह चौहान ने दिवाकर भट्ट के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन को निर्वाहिक साधु देने के इस योगदान के लिए हमेशा राज्यवासियों के मनमस्तिक में अंकित रहेंगे।

दिवाकर भट्ट का निधन उत्तराखंड के लिए बड़ा झटका: धीरे-धीरे प्रताप देहरादून

देहरादून। उत्तराखण्ड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री और विजित राज्य आंदोलनकारी संस्कृति समिति के कर्तव्य मुख्य संस्थापक धीरे-धीरे प्रताप ने उत्तराखण्ड क्रांति दल के नेता फील्ड मशीन दिवाकर भट्ट के निधन पर गहरा दुःख और शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनके निधन राज्य निर्माण आंदोलन को निर्वाहिक साधु देने के इस योगदान के लिए हमेशा राज्यवासियों के मनमस्तिक में अंकित रहेंगे।

दिवाकर भट्ट का नाम उत्तराखण्ड आंदोलन का इतिहास अथवा माना जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अपने समय के खोजू नेता थे। उन्होंने सदैव राज्य गठन के अपने संघर्ष को निजी स्वार्थ से ऊपर रखा और निरंतर राज्य आंदोलन का योगदान प्रत्येक नेतृत्व करके राज्य निर्माण आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि उनके निधन से उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन को बड़ा झटका लगा है।

श्रीराम मंदिर का पूर्णत्व, सनातन संस्कृति के स्वर्णिम युग का आगाज: भट्ट

कहा - युगों युगों तक यह सनातन धर्मस्थल, विश्व कल्याण का संदेश फैलाती रहेगी

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यभा सोसाइटी महेंद्र भट्ट ने भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख मनवीर सिंह चौहान ने दिवाकर भट्ट के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन को निर्वाहिक साधु देने के इस योगदान के लिए हमेशा राज्यवासियों के मनमस्तिक में अंकित रहेंगे।

भाब, अविचल आस्था, अतुलनीय धैर्य और अविस्मरणीय बलिदानों का साकार रूप है। एक राजनैतिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे प्यार है कि सनातन संस्कृति की राखनी में इस अभूतपूर्व इतिहास की पुनर्स्थापना में हमारी पार्टी के अनेकों सदस्यों ने अपने सर्वस्व का बलिदान दिया है। आज दुनिया का सनातन संस्कृति और परम्परा के पुनरुत्थान का यह युग हुआ है, जिसमें सभी धर्म बलिदान, निर्यात के प्रयासों को पूर्णतः ही है (उन्होंने विचारवा जताते हुए कहा, आने वाले इबारों सालों तक प्रभु श्री राम का यह मंदिर, विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। यहां मौल दिवाकर भट्ट का यह धर्म बलिदान, दुनिया भर में हिंदू धर्म की कीर्ति संरक्षण पाने का कहनायें में प्रेरणादायक साक्ष्य होगी।

परायवरण, सेवा, खेल, तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर गहन मन-चिंतन होगा और प्रस्ताव समिति द्वारा देशभर से प्राण विभिन्न सुझावों पर चिंतन करके उन्हें पारित किया जाएगा। भावविष के विचार वृक्ष, संगठन के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अभियान, स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुष, संस्कृति पुनर्जागरण की विधित्ता तथा विशेष रूप से रानी अम्बिका के साहस को प्रभावशाली रंग से प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शन उद्घाटन के पछा अतिथि आचार्य बालकृष्ण होंगे। एप्रिल के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि, आचार्य का यह 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन इसलिए ही विशेष है। देवभूमि उत्तराखण्ड में पहली बार यह राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। इस आयोजन की तैयारी के लिए उत्तराखण्ड में सैकड़ों कार्यकर्ता लगे हैं, जो कि देशभर से आ रहे 1500 से अधिक प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे।



चार श्रम संहिताएं हुईं लागू

“देश को अपनी श्रम-शक्ति पर गर्व है। श्रमेव जयते।”

— प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

मोदी सरकार की गारंटी युवा कामगारों के लिए

- सभी कामगारों को समय पर न्यूनतम वेतन
- सभी कामगारों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र
- कैलेंडर वर्ष में 180 दिन काम करने पर वार्षिक वेतन सहित अवकाश का प्रावधान
- निश्चित अवधि के कामगारों को स्थायी कामगारों के समान लाभ मिलेंगे; सर्विस के एक साल बाद ही ग्रेजुटी का प्रावधान



28 नवंबर से शुरू होगा एबीवीपी का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 28 से 30 नवंबर को देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में अर्थात् रूप से स्थापित रणभावन विरसा मुंडा नगर में आयोजित होगा। जिसमें देशभर से 1500 से अधिक प्रतिनिधि, जिनमें विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षाविद, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के साथ भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों के छात्रसंघ प्राधिकारी भी शामिल होंगे।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों, सत्रों और प्रदर्शनों को स्थान दिया है। अधिवेशन के मुख्य सभापति का नाम भारतीय संसद के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। साथ ही, अधिवेशन से पूर्व होने वाली महत्वपूर्ण यात्राओं में विरसा मुंडा की 150वां जन्म जयंती पर



1500 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल परेड ग्राउंड में बनाए गए विरसा मुंडा नगर में प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा मुख्य सभापति

इस अधिवेशन में लाया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ आगामी 28 नवंबर को होगा, जिसके उद्घाटन सत्र में इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। अधिवेशन में अभाविप के संगठन विस्मृति प्रा. यमरिंदर केलकर की स्मृति में युवा पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा। भगवान कल्याण में महती भूमिका निभाने वाले गोरखपुर के श्रीकृष्ण पाण्डेय को ‘भगवान कल्याण कलक पुरस्कार’ से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान विरसा मुंडा नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। अधिवेशन के दौरान शिक्षा, समाज,

ल
के
के
त
न
मं
भ
जी
न
त
में
के
ओं
ट
ए
र
मं
में
त,
ट,
ग.

मुजफ्फरनगर न्यायालय के अधीन ही होंगे।

शाह टाइम्स

सम्पादकीय

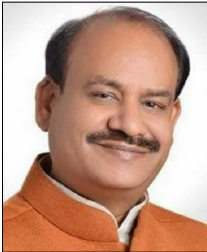
बुधवार, 26 नवम्बर 2025

एसआईआर का जाल

बिहार चुनाव के बाद देश के बारह राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। इसकी जिम्मेदारी उन बीएलओ को दी गई है, जो लोकतंत्र का एक हिस्सा हैं। लेकिन सरकार उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर रही हैं। ये बीएलओ घर-घर जाकर दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं और मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाने में जुटे हैं। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है। लेकिन जाल ऐसा हो गया है कि बीएलओ का उसमें से निकलना मुश्किल हो रहा है। नतीजतन देश के अलग अलग राज्यों में 16 बीएलओ की मौत हो गई। सरकार की इस प्रक्रिया पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और आम जनता भी कई दिक्कतों का सामना कर रही है। इन सबके बीच हम उन बीएलओ को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं, जो इस अभियान में सबसे सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इन्हें लोकतंत्र के सच्चे सिपाही कहा जा सकता है, लेकिन यही सिपाही इस समय परेशान हैं, दबाव में हैं, डर में जी रहे हैं और कई ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। ये सभी बीएलओ वर्तमान में किसी न किसी स्कूल में शिक्षक, शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत हैं। कई तो ऐसे हैं जो कई चुनाव देख चुके हैं, जिन्होंने हर बार बिना सवाल किए सरकार के आदेशों का हर बार पालन किया है, लेकिन इस बार जमीन पर मिसमैनेजमेंट ऐसी है कि ये शिक्षक भी त्रस्त हो चुके हैं। दूसरी तरफ अधिकारियों द्वारा काम समय से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। एक बीएलओ ने दावा किया कि उन्हें टारगेट पूरा न करने पर एफआईआर किए जाने की धमकी दी गई। चुनाव आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि किसी बीएलओ ने सही प्रकार से काम नहीं किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेहतर होता कि सरकार इन्हें पहले संसाधन उपलब्ध कराती और फिर कार्यभार सौंपती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि 21 नवंबर की रात से 22 नवंबर के मध्य प्रदेश में दो बीएलओ की बीमारी के कारण मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में नदिया में बीएलओ रिक्रू का शव घर की छत से लटका मिला। राज्य में एसआईआर से जुड़ा दूसरा सुसाइड, तीसरी मौत है। राजस्थान के जयपुर में रविवार को बीएलओ मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। करौली में बीएलओ की मौत हो गई। सवाई माधोपुर में एक बीएलओ को हार्ट अटैक से मौत हो गई। मध्य प्रदेश में एक रात में 2 बीएलओ की मौत हो गई और एक लापता हो गया, जबकि दो को हार्ट अटैक आया। देश में एसआईआर का इतना विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसी से दुखी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पैदल मार्च निकालना शुरू कर दिया है। सरकार को चाहिए कि एक बार फिर वह इस बारे में सोच और कोई सकारात्मक समाधान निकाले।

हमारे देश की आत्मा है संविधान

भारत का संविधान दुनिया के अन्य देशों के लिए भी मार्गदर्शक है, संविधान को जानो, अपनाओ और संविधान के अनुसार जियो, हमारे देश में बोली, भाषा, खानपान सहित अनेक विविधताएं हैं, लेकिन देश की समस्त विविधताओं को एक करने का काम हमारा संविधान करता है, हर विद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षण पाठ्यक्रम में संविधान का अध्ययन होना चाहिए भारत का संविधान दुनिया के अन्य देशों के लिए भी मार्गदर्शक है और यह हमारे देश की आत्मा है।



–ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष

ए आईएमआईएम के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करना एक मुश्किल काम है क्योंकि उसे मुसलमानों को अपनी क्षमता का एहसास दिलाना होगा, जबकि सपा अभी तक इस समुदाय पर ऑक्टोपस जैसा नियंत्रण रखती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि एआईएमआईएम, गठबंधन में या अकेले, भाजपा विरोधी वोटों को बांट पाती है या नहीं और इससे हिंदुत्व समर्थक ताकतों को एकजुट करने में भी मदद मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2027 के चुनावी संग्राम की ओर बढ़ रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव में 1.85 प्रतिशत वोटों के साथ पांच सीटें जीतने के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की राह में रोड़ा अटकाने की धमकी दी है। हालांकि, अपनी पार्टी के लिए मुस्लिम समर्थन की जमीनी हकीकत को अच्छी तरह से जानते हुए अखिलेश यादव ने अब तक ओवैसी के बयानों पर चुप्पी साधे रखी है। हालांकि बिहार में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद, उत्तर प्रदेश में 2027 के भारतीय गठबंधन का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं है, फिर भी सपा 2027 में पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन को लेकर बेहद सतर्क है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) तथा कुछ अलग-अलग गुटों के बीच एक व्यापक गठबंधन था। हालांकि, कांग्रेस केवल दो सीटें ही जीत पाई और रालोद आठ सीटें (2.9 प्रतिशत वोट) जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गई। लगभग 33 प्रतिशत वोटों के साथ सपा ने 111 सीटें जीती थीं। तब एआईएमआईएम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। मुस्लिम समुदाय, जो सपा के साथ मजबूती से खड़ा था, ने एआईएमआईएम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। एआईएमआईएम ने 103 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसे केवल 0.49 प्रतिशत वोट मिले। उसे सबसे ज्यादा वोट 36460 (16.27 प्रतिशत) आजमगढ़ के मुबारकपुर से मिले थे, जहां से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली मैदान में थे। गुड्डू जमाली विधानसभा में बसपा के नेता प्रतिपक्ष थे और चुनाव से पहले सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन सपा से टिकट न मिलने पर वे एआईएमआईएम में शामिल हो गए। यह गुड्डू जमाली की व्यक्तिगत छवि ही थी जिसने एआईएमआईएम को भारी वोट दिलाए। इसलिए, बसपा, एआईएमआईएम और कुछ छोटे दलों के तीसरे मोर्चे की किसी भी

यूपी विधानसभा चुनावों में ओवैसी का अखिलेश यादव से मुलाकात का वादा

रामगढ़ में बसपा उम्मीदवार के जुलूस में एआईएमआईएम के बैनर भी देखे गए। खबर है कि एआईएमआईएम ने अपने समर्थकों से उन जगहों पर बसपा को वोट देने की अपील की जहां उसका कोई उम्मीदवार नहीं था। जबकि बिहार में एआईएमआईएम का चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टियों के साथ गठबंधन था। बिहार में बसपा का कुल वोट प्रतिशत 1.62 रहा। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपना दल की पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि जून 2021 में एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के बाद मायावती ने कहा था, शयद खबर पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और निराधार है।



एम हसन

संभावना की कल्पना करना अभी जल्दबाजी होगी। बसपा प्रमुख मायावती पहले ही यूपी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। 2022 में, एआईएमआईएम ने छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की कोशिशें की थीं, लेकिन यह कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। अब बिहार में बसपा और एआईएमआईएम के बीच बहुचर्चित अप्रत्यक्ष गठबंधन के बाद, जहां बसपा विजेता सतीश यादव रामगढ़ ने जीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती के साथ ओवैसी के पोस्टर लगाए थे, यूपी में दोनों दलों के सपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ आने की कहानी गढ़ी जा रही है।

रामगढ़ में बसपा उम्मीदवार के जुलूस में एआईएमआईएम के बैनर भी देखे गए। खबर है कि एआईएमआईएम ने अपने समर्थकों से उन जगहों पर बसपा को वोट देने की अपील की जहां उसका कोई उम्मीदवार नहीं था। जबकि बिहार में एआईएमआईएम का चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टियों के साथ गठबंधन था। बिहार में बसपा का कुल वोट प्रतिशत 1.62 रहा। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपना दल की पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि जून 2021 में एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के बाद मायावती ने कहा था, शयद खबर पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और निराधार है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। मायावती ने तब 2022 में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया था और वह अपने इस रुख पर अड़ी रहें। लेकिन अब मायावती उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करने की पुर्जोर को।

शिशु कर रही हैं और ओवैसी भाजपा की बी टीम के ठप्पे से छुटकारा पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। यह तभी संभव होगा जब वह बसपा के साथ गठबंधन करने में कामयाब हो जाएं। हालांकि, बसपा सूत्रों ने बताया कि वह अपने मूल वोट बैंक जाटवों की प्रतिक्रिया का आकलन कर रही हैं, जिनकी ग्रामीण इलाकों में मुसलमानों के साथ नजदीकियां बहुत अच्छी नहीं रही हैं, चूंकि इस बहुचर्चित गठबंधन का व्यापक प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से लेकर सहारनपुर तक लगभग 100 सीटों पर पड़ सकता है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जाटव एआईएमआईएम को वोट देने के लिए तैयार होंगे। एआईएमआईएम की तरह, उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समुदाय भी बसपा को भाजपा की बी टीम मानता है।

नाम न छापने की शर्त पर एक सपा नेता ने कहा, इसलिए दो बी टीमों सपा से मुकाबला करने के लिए एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए एक साथ आने की कोशिश कर रही हैं। बिहार में बसपा का कुल वोट प्रतिशत 1.62 रहा। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपना दल की पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। गौरतलब है कि जून 2021 में एक समाचार चैनल की रिपोर्ट के बाद मायावती ने कहा था, शयद खबर पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और निराधार है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। मायावती ने तब 2022 में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया था और वह अपने इस रुख पर अड़ी रहें। लेकिन अब मायावती उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करने की पुर्जोर को।

विपक्ष मुक्त लोकतंत्र के दुष्प्रयास अभी भी जारी

7 जून 2013 को गोवा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनाव अभियान समिति की बैठक के दौरान जिस समय नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनावों के लिए अभियान समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया उस समय उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हमारा सपना होना चाहिए। इस आह्वान के फौरन बाद उन्होंने दिवटर पर भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा था कि वरिष्ठ नेताओं ने मुझ में विश्वास जताया है। हम कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद से अब तक वे इसी बात को दूसरे शब्दों में अपनी चुनावी संभाओं या सार्वजनिक रैलियों आदि में कहते रहते हैं। जैसे कभी देश को फ्रांघ्रेस संस्कृति से मुक्ति दिलाने की बात कभी पजे से मुक्ति, कभी तुष्टिकरण से मुक्ति तो कभी परिवारवाद व भ्रष्टाचार से मुक्ति के रूप में देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस को कोसकर विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की अपनी हसरत की अभिव्यक्ति करते रहे हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 99 सीटें आने के बाद मोदी की इस हसरत पर विराम लग गया था। फिर भी कांग्रेस के दर्जनों नेताओं को थप लालच आदि के द्वारा अपने पाले में कर कांग्रेस को पूरी तरह कमजोर करने की कोशिश जरूर की गई। अब बिहार चुनाव परिणामों से उत्साहित भाजपा दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक एक बार फिर कांग्रेस व विपक्ष को

कमजोर करने की कोशिश करने लगी है। इसी उद्देश्य से पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने सूत्र में एक कार्यक्रम के दौरान फिर एक बयान दिया है। इस बार मोदी ने कांग्रेस व अन्य विपक्षी सांसदों की पैरवी करते हुए उनके राजनीतिक कैरियर के प्रति चिंता जाहिर की है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के युवा सां. सदों को पार्टी नेतृत्व बोलने नहीं देता, जिससे उनका राजनीतिक कैरियर बर्बाद हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसद मुझसे मिलते हैं, तो वे कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारा कैरियर खत्म हो रहा है। हमें संसद में बोलने का मौका ही नहीं मिलता। हर बार यही कहा जाता है कि संसद को ताला लगा दो। उन्होंने कांग्रेस पर और भी हमले किए। मोदी द्वारा विपक्षी सांसदों को फिर्क किए जाने के सन्दर्भ में यह सोचना जरूरी है कि अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं का बना बनाया कैरियर समाप्त करने या उन्हें अज्ञातवास अथवा राजनैतिक संन्यास पर भेजने के लिए मजबूर करने वाले प्रधानमंत्री मोदी को आखिर विपक्षी सांसदों के कैरियर की चिंता कैसे सताने लगी? गुजरात से लेकर दिल्ली तक कितने नेताओं को दरकिनार कर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले मोदी को विपक्षी सांसदों के कैरियर की चिंता सताने लगी? लाल कूष्ण आडवाणी ने तो खुद मोदी जी का कैरियर बचाने में उनकी मदद की थी। याद कीजिए 2002 के गुजरात दंगों के बाद तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल

बिहारी वाजपेई ने मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटाने की ठान ली थी। उस समय आडवाणी ने ही मोदी का साथ देकर इन की कुर्सी बचाई थी। बाद में मोदी ने आडवाणी जी को कहा पहुंचा दिया ? जिनके पैर छुआ करते थे उन्हें ऐसे मार्ग दर्शन मंडल में भेज दिया जहां से मार्ग दर्शन लेने की किसी को जरूरत ही नहीं होती? मुरली मनोहर जोशी का वाराणसी से टिकट काट कर पहले खुद चुनाव लड़ा बाद में उन्हें भी मार्ग दर्शन मंडल का रास्ता दिखा दिया? मार्गदर्शन मंडल के बारे में बताया गया कि 75 की आयु पार करने वालों को इसमें स्थान मिलेगा परन्तु स्वयं 1950 में जन्मे मोदी भी आज 75 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं।

तो क्या 75 के नाम पर अपने अनेक वरिष्ठ नेताओं का कैरियर चौपट करने वाले मोदी जी को स्वयं अपनी आयु 75 होने पर मार्गदर्शक मंडल का रास्ता नजर नहीं आता? केंद्र में 79 वर्षीय जीतन राम मांझी मंत्री बनाए जा सकते हैं। 83 वर्षीय आनंदीबेन पटेल व 81 वर्षीय आचार्य देवव्रत राज्यपाल बनाए जा सकते हैं परन्तु सुब्रमण्यम स्वामी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी जैसे नेताओं के कैरियर की कोई फिर्क नहीं ? ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि मोदी को अपने राजनैतिक कैरियर के सिवा किसी और के राजनैतिक कैरियर की कोई फिर्क नहीं होती। लंबे समय तक भाजपा में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद कहा था कि भाजपा



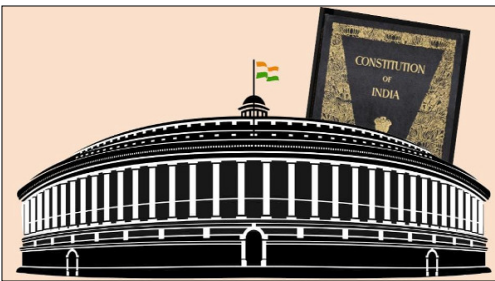
तनवीर जाफरी

में अब लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह को बिहार चुनाव परिणाम आते ही इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने न केवल पार्टी के अपराधी नेताओं को पार्टी प्रत्याशी बनाने पर सवाल खड़ा किया था बल्कि अडानी पावर व नीतीश सरकार के बीच हुए कथित 62,000 करोड़ रूपए के बिजली घोटाले का भी खुलासा किया था और इस घोटाले की जांच की मांग की थी। इसलिए कांग्रेस या विपक्षी सांसदों के कैरियर को लेकर चिंतित होना दरअसल उनके कैरियर की चिंता करना नहीं बल्कि अपनी इन कथित चिंताओं का प्रदर्शन कर कांग्रेस व विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश मात्र है। कुछ ऐसी ही कोशिशें इन दिनों लालू यादव के परिवार में पड़ी पारिवारिक फूट को लेकर देखी जा रही हैं। यहां भी लालू –तेजस्वी का विरोध करने वाले परिवार के सदस्यों को हवा देने की खबरें आ रही हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों को समाहित करता है भारतीय संविधान

26 नवम्बर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, जो वास्तव में भारत के लोकतांत्रिक स्वाभिमान का उत्सव है। संविधान सभा ने इसी दिन वह महान दस्तावेज अपनाया था, जिसने हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा का आश्वासन दिया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की दूरदर्शिता और डॉ. संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें ‘भारतीय संविधान के निर्माता’ के रूप में जाना जाता है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हमारा संविधान न केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है बल्कि उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। हालांकि इसे स्वीकृत 26 नवम्बर 1949 को ही कर लिया गया था। इसीलिए 26 नवम्बर को ही ‘संविधान दिवस’ मनाया जाता है। यह अवसर हमें



संविधान को प्रति सम्मान व्यक्त करने और इसके आदर्शों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें हमारे संविधान और उसकी विशेषताओं की याद दिलाता है। दरअसल भारतीय संविधान ने देश को एक ऐसा ढांचा प्रदान किया, जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। यह दिवस हमें संविधान निर्माताओं के योगदान और उनकी मेहनत को याद करने का अवसर देता है। संविधान निर्माण की मांग का इतिहास 19वीं सदी के अंत से ही शुरू हो गया था। सन् 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह मांग की थी कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। उनके सहयोगियों द्वारा तैयार किए गए स्वराज्य विधेयक को प्रारूप में ब्रिटिश सरकार ने टुकरा दिया था। वह पहली बार था, जब स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की बात उठाई गई थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था

कि भारत का राजनैतिक भविष्य भारतीय स्वयं तय करेंगे। उसी के तहत 1924 में पं। मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग उठाई। हालांकि, वह मांग भी अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी। उसके बाद संविधान सभा की मांग लगातार उठती रही लेकिन ब्रिटिश सरकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान की निर्माण केवल संविधान सभा द्वारा ही किया जा सकता है। इसके बाद 1940 में ब्रिटिश सरकार ने उस मांग को स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया जाएगा। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्रिप्स कमीशन का गठन किया। क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करेगी। यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 9 दिसंबर 1946 को सिन्धुद्वन्द्व सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। हालांकि, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर उस बैठक का बहिष्कार किया। इसके बावजूद संविधान निर्माण की प्रक्रिया जारी रही। 11

दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉ। राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थाई अध्यक्ष चुना गया। वे संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान इस पद पर बने रहे। उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और संविधान का प्रारूप तैयार किया। 14 अगस्त 1947 को भारत डोमिनियन की प्रभुता सम्पन्न संविधान सभा ने पुनः बैठक की। उस बैठक में 29 अगस्त 1947 को संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया और डॉ. भीमराव अंबेडकर को सर्वसम्मति से उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। संविधान प्रारूप समिति की बैठकें कुल 114 दिनों तक चली। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न वर्गों, समुदायों और संगठनों के सुझावों को ध्यान में रखा गया। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस कार्य पर कुल 63 लाख 96 हजार 729 रूपए का खर्च हुआ। यह अपने आप में एक विशाल और जटिल कार्य था, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों ने दिन-रात कड़ी मेहनत की। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 7635 सूचनाओं पर चर्चा की गई। भारत के संविधान को भारत की विविधता और एकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया, जो विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को समाहित करता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें विभिन्न विषयों को विस्तारपूर्वक शामिल किया गया है। संविधान में भारत



अतुल गोयल

को एक संघीय राज्य घोषित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान नागरिकों को छह प्रमुख मूल अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदाई होती है। भारतीय संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने की व्यवस्था करता है। संविधान में समय-समय पर संशोधन की व्यवस्था की गई है ताकि इसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखा जा सके। भारत का संविधान लागू हुआ था और उसके बाद से संविधान में कई संशोधन किए गए हैं। अब तक इसमें 440 से भी अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हो चुकी हैं। भारतीय संविधान समय के साथ बदलते सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

यौन समस्याएं

यौन समस्याओं के विशेषज्ञ

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

डा. सम्राट

नशामुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन कैप्सूल अपीम, चरस, डोडे पोस्ट इंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज ।

नावल्टी सिनेमा चौक
मुजफ्फरनगर (यू.पी.)

M-9412211108